



8 अक्तूबर 2021

गवर्नर का वक्तव्य : 8 अक्तूबर 2021

महामारी की शुरुआत के बाद से यह मेरा बारहवां वक्तव्य है। इनमें से दो वक्तव्य मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) चक्र से बाहर थे - एक अप्रैल 2020 में कोविड-19 संकट के प्रकोप पर और दूसरा मई 2021 में दूसरी लहर के चरम पर। इसके अलावा, दो अवसरों पर - मार्च और मई 2020 - एमपीसी की बैठक को अर्थव्यवस्था को महामारी के कहर से बचाने के लिए पूर्वक्रीत कार्य करने के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। इस अवधि के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अद्वितीय संकट से निपटने के लिए सक्रिय और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए 100 से अधिक उपाय किए हैं। ऐसा करते हुए हम किसी नियम-पुस्तिका के बंदी नहीं रहे हैं। हमने वित्तीय बाजारों के कामकाज और बाजार की धारणा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए नए और अपरंपरागत उपाय करने; लक्षित क्षेत्रों और संस्थानों को तरलता प्रदान करने; और व्यक्तियों और व्यवसायों तक पहुंचने के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने में संकोच नहीं किया है। इस प्रकार, हालांकि महामारी के प्रोटोकॉल हमें अलग करते हैं, प्रौद्योगिकी हमें एक साथ बांधती है।

2. इस पृष्ठभूमि में, एमपीसी की बैठक 6, 7 और 8 अक्टूबर 2021 को हुई। उभरती समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों और दृष्टिकोण के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति से वोट किया और उदार नीति रुख को बनाए रखने के लिए 5 से 1 के बहुमत से वोट किया। परिणामस्वरूप, पॉलिसी रेपो दर 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहती है; और जब तक टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने और अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है, तब तक निभावकारी रुख बना रहेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति आगे भी लक्ष्य के भीतर बनी रहे। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है। रिवर्स रेपो दर भी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

3. हमारे पीछे दूसरी लहर की सबसे खराब स्थिति और कोविड-19 टीकाकरण में पर्याप्त वृद्धि के साथ, आर्थिक गतिविधियों को खोलने और सामान्य करने के लिए अधिक विश्वास देने के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था की बहाली कर्षण प्राप्त कर रही है। जबकि वर्तमान वैश्विक सुधार में वैक्सीन की पहुंच वास्तविक दोष रेखा है, भारत पिछली एमपीसी बैठक के समय की तुलना में आज बहुत बेहतर स्थिति में है। विकास के आवेग मजबूत होते दिख रहे हैं और हमें इस तथ्य से आराम मिलता है कि मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र अनुमान से अधिक अनुकूल हो रहा है। वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद, हम भारतीय अर्थव्यवस्था के वृहद-आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के अंतर्निहित लचीलेपन द्वारा संचालित, तूफान से उभरने और सामान्य समय की ओर बढ़ने की उम्मीद करते हैं।

4. अब मैं नीतिगत दर पर विराम और निभावकारी रुख के लिए एमपीसी के औचित्य का संक्षिप्त विवरण देता हूं। एमपीसी ने नोट किया कि पिछले दो महीनों में आर्थिक गतिविधि एमपीसी के अगस्त मूल्यांकन और दृष्टिकोण के अनुरूप व्यापक रूप से विकसित हुई है; और जुलाई-अगस्त के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान से कम हो गई है। 2021-22 की पहली तिमाही में 20.1 प्रतिशत पर वास्तविक जीडीपी वृद्धि का वास्तविक परिणाम करीब था, हालांकि एमपीसी के 21.4 प्रतिशत के पूर्वानुमान से थोड़ा कम था। 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए उच्च-आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि आर्थिक सुधार में गति आई है जो संक्रमण में कमी, टीकाकरण की मजबूत गति, अपेक्षित रिकॉर्ड खरीफ खाद्यान्न उत्पादन, पूंजीगत व्यय पर सरकार का ध्यान, सौम्य मौद्रिक और वित्तीय स्थिति, और उत्साही बाहरी मांग द्वारा समर्थित है।
5. जुलाई-अगस्त के दौरान उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में नरमी आई, खाद्य मुद्रास्फीति में ढील के साथ सहिष्णुता बैंड में वापस जाते हुए, मई में मुद्रास्फीति में वृद्धि के एमपीसी के आकलन को क्षणभंगुर के रूप में पुष्टि की गयी। सितंबर में मानसून में सुधार, अपेक्षित उच्च खरीफ उत्पादन, खाद्यान्नों का पर्याप्त बफर स्टॉक और सब्जियों की कीमतों में कम मौसमी तेजी से खाद्य कीमतों का दबाव कम रहने की संभावना है। हालांकि, मूल मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि, प्रमुख औद्योगिक घटकों की भारी कमी और उच्च रसद लागत के साथ मिलकर, इनपुट लागत दबाव बढ़ा रहे हैं। हालांकि, कमजोर मांग की स्थिति के कारण आउटपुट कीमतों के लिए पास-श्रू को रोक दिया गया है। उभरती स्थिति के लिए निकट सतर्कता की आवश्यकता है।
6. कुल मिलाकर, कुल मांग में सुधार हो रहा है लेकिन सुस्त अभी भी बना हुआ है; उत्पादन अभी भी पूर्व-महामारी स्तर से नीचे है और वसूली असमान बनी हुई है और निरंतर नीति समर्थन पर निर्भर है। संपर्क गहन सेवाएं, जो भारत में आर्थिक गतिविधियों में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान करती हैं, अभी भी पिछड़ रही हैं। आपूर्ति पक्ष और लागत-प्रेरित दबाव मुद्रास्फीति पर प्रभाव डाल रहे हैं और आपूर्ति श्रृंखलाओं के चल रहे सामान्यीकरण के साथ इनके सुधारने की उम्मीद है। ईंधन पर अप्रत्यक्ष करों के अंशशोधित रिवर्सल के माध्यम से लागत-प्रेरित दबावों को नियंत्रित करने के प्रयास, मुद्रास्फीति को और अधिक निरंतर कम करने और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर करने में योगदान कर सकते हैं। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, एमपीसी ने मौजूदा रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने और निभावकारी रुख को जारी रखने का निर्णय लिया, जैसा कि पिछले एमपीसी वक्तव्य में कहा गया है।

विकास और मुद्रास्फीति का आकलन

विकास

7. 31 अगस्त को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार, 2021-22 की पहली तिमाही में 20.1 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि ने कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर के सामने

अर्थव्यवस्था के लचीलापन को प्रदर्शित किया। दूसरी लहर के कारण गति के तेज नुकसान के बावजूद, सकल घरेलू उत्पाद के लगभग सभी घटकों ने वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की।

8. अगस्त-सितंबर में कुल मांग में बहाली में तेजी आई। यह उच्च आवृत्ति संकेतकों में परिलक्षित होता है - रेलवे माल यातायात; बंदरगाह कार्गो; सीमेंट उत्पादन; बिजली की मांग; ई-वे बिल; जीएसटी और टोल वसूली। संक्रमण में कमी, उपभोक्ता विश्वास में सुधार के साथ, निजी खपत का समर्थन कर रही है। वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में दाबी हुई मांग और त्योहारी सीजन से शहरी मांग में और तेजी आनी चाहिए। पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में कृषि क्षेत्र के निरंतर लचीलेपन और खरीफ खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन से ग्रामीण मांग को गति मिलने की उम्मीद है। जलाशयों के स्तर में सुधार और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जल्द घोषणा से रबी उत्पादन की संभावनाएं बढ़ी हैं। सरकारी खपत से कुल मांग को समर्थन भी गति पकड़ रहा है।
9. अनुकूल वित्तीय स्थितियों के साथ-साथ सरकारी पूंजीगत व्यय में सुधार, बहुप्रतीक्षित पुण्य निवेश चक्र में तेजी ला सकता है। पूंजीगत वस्तुओं के आयात और सीमेंट उत्पादन में वृद्धि निवेश गतिविधि में कुछ पुनरुद्धार की ओर इशारा करती है। हमारे सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू), जिसमें दूसरी लहर के तहत Q1: 2021-22 में तेजी से गिरावट आई, का अनुमान है कि वह दूसरी तिमाही में बहाल हो गया है और आगामी तिमाहियों में और सुधार की उम्मीद है।
10. कुल मांग को महत्वपूर्ण समर्थन निर्यात से भी मिला, जो सितंबर 2021 में लगातार सातवें महीने 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा, जो मजबूत वैश्विक मांग और नीतिगत समर्थन को दर्शाता है। यह 2021-22 के दौरान 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हमारे निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के लिए शुभ संकेत है।
11. सेवा क्षेत्र में रिकवरी भी जोर पकड़ रही है। प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के साथ-साथ संपर्क-गहन सेवाओं में धीरे-धीरे वृद्धि से गति को समर्थन देने की संभावना है।
12. लाभ मार्जिन पर उच्च इनपुट लागत का प्रभाव, संभावित वैश्विक वित्तीय और कमोडिटी बाजारों में अस्थिरता और कोविड-19 संक्रमणों का फिर से उभरना, हालांकि, विकास के दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम प्रदान करते हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 2021-22 में 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जिसमें Q2 में 7.9 प्रतिशत; Q3 में 6.8 प्रतिशत; और 2021-22 की चौथी तिमाही में 6.1 प्रतिशत शामिल है। 2022-23 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 17.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति

13. हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति अगस्त में 5.3 प्रतिशत पर लगातार दूसरे महीने साधारण रही और जून 2021 में अपने स्तर से एक प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज की गई। अवस्फीति का प्रमुख चालक खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी रहा है, भले ही ईंधन मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई और खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति (मुख्य मुद्रास्फीति) को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति ऊंची बनी रही। खाद्य तेल, पेट्रोल और डीजल, एलपीजी और दवाओं जैसी चुनिंदा वस्तुओं में बहुत अधिक मुद्रास्फीति से हेडलाइन मुद्रास्फीति महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुई है। दूसरी ओर, सब्जियों की कीमतों में बहुत कम मौसमी निर्माण, अनाज की कीमतों में गिरावट, सोने की कीमतों में तेज गिरावट और सुस्त आवास मुद्रास्फीति ने मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने में मदद की है।
14. आगे बढ़ते हुए, कई उभरते कारक खाद्य मूल्य के मोर्चे पर सहूलियत प्रदान करते हैं। निकट भविष्य में इसकी गति मंद रहने की उम्मीद है। रिकॉर्ड खरीफ खाद्यान्न उत्पादन और पर्याप्त बफर स्टॉक के कारण अनाज की कीमतें नरम रहने की उम्मीद है। सरकार द्वारा रिकॉर्ड उत्पादन और आपूर्ति पक्ष उपायों के साथ, सब्जियों की कीमतें, जो मुद्रास्फीति की अस्थिरता का एक प्रमुख स्रोत है, वर्ष में अब तक नियंत्रित रही हैं। हालांकि, आने वाले महीनों में बेमौसम बारिश और प्रतिकूल मौसम संबंधी घटनाएं - यदि कोई हो - सब्जियों की कीमतों में तेजी के जोखिम हैं। खाद्य तेलों और दालों के लिए सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष उपाय कीमतों के दबाव को कम करने में मदद कर रहे हैं; हालांकि, हाल की अवधि में खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी देखी गई है।
15. कुल मिलाकर, सीपीआई हेडलाइन गति कम हो रही है, जो आने वाले महीनों में अनुकूल आधार प्रभावों के साथ, निकट अवधि में मुद्रास्फीति में पर्याप्त नरमी ला सकती है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2021-22 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.3 प्रतिशत: दूसरी तिमाही में 5.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.5 प्रतिशत; व्यापक रूप से संतुलित जोखिमों के साथ 2021-22 की चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत अनुमानित है। 2022-23 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हम विकसित हो रही मुद्रास्फीति की स्थिति के प्रति सतर्क हैं और इसे धीरे-धीरे और गैर-विघटनकारी तरीके से लक्ष्य के करीब लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

16. वर्तमान समय में, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक खुद को चौराहे पर पा रहे हैं। मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव देश समूहों द्वारा नहीं बल्कि देश की परिस्थितियों द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से कुछ मौद्रिक नीति को सख्त कर रहे हैं, अन्य आगे मौद्रिक प्रोत्साहन दे रहे हैं, जबकि कुछ दृढ़ विराम पर हैं। मौद्रिक नीति को सख्त करने वाले देश वे हैं जो अपने ऊपरी सहनशीलता बैंड से बहुत ऊपर मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं और पूर्व-महामारी स्तरों से ऊपर संवृद्धि में एक मजबूत प्रतिक्षेप दर्ज कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक आर्थिक स्थितियों में सुधार से कमोडिटी निर्यात आय और सकारात्मक स्पिलओवर द्वारा बढ़ाया गया है। गैर-दर कार्रवाइयों के माध्यम से मौद्रिक नीति को आसान बनाने वाले देश बहुत

कम हैं, जिनकी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति कम है। और अंत में, जो देश एक दृढ़ विराम पर हैं, उनकी मुद्रास्फीति ऊंचाई पर है लेकिन संवृद्धि की खराब संभावनाएं हैं या नवजात बहाली को पोषण की आवश्यकता है। भारत में, एमपीसी ने ठहराव बनाए रखा है और समय-समय पर निभावकारी बनाए रखने के लिए समय और राज्य आकस्मिक आगे के लिए मार्गदर्शन दिया है। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन हमारी घरेलू परिस्थितियों और हमारे आकलन के लिए उन्मुख बना रहेगा।

17. महामारी की शुरुआत के बाद से, रिज़र्व बैंक ने एक त्वरित और टिकाऊ आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त अधिशेष चलनिधि बनाए रखी है। बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि का स्तर सितंबर 2021 के दौरान और बढ़ गया, जिसमें स्थायी दर रिवर्स रेपो, 14 दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) के तहत अवशोषण और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत फाइन-ट्यूनिंग ऑपरेशन जून से अगस्त 2021 के दौरान ₹7.0 लाख करोड़ की तुलना में प्रति दिन औसतन ₹9.0 लाख करोड़ था। अधिशेष चलनिधि अक्टूबर में अब तक (6 अक्टूबर तक) दैनिक औसत ₹9.5 लाख करोड़ तक बढ़ गई। संभावित चलनिधि आगे बढ़ी हुई राशि ₹13.0 लाख करोड़ से अधिक है।
18. जैसा कि अर्थव्यवस्था कोविड-19 के प्रकोप से उभरने के संकेत दिखाती है, बाजार सहभागियों और नीति निर्माताओं के बीच एक आम सहमति का दृष्टिकोण उभर रहा है कि संकट के दौरान स्थापित असाधारण उपायों से उत्पन्न चलनिधि की स्थिति को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए समष्टिआर्थिक विकास के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया को धीरे-धीरे, अंशांकित और गैर-विघटनकारी होना चाहिए, जबकि आर्थिक बहाली के लिए सहायक बने रहना है।
19. रिज़र्व बैंक का द्वितीयक बाजार सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) बाजार की समस्याओं को दूर करने और सरकार के बड़े उधार कार्यक्रम के संदर्भ में प्रतिफल अपेक्षाओं को स्थिर करने में सफल रहा है। अन्य चलनिधि उपायों के साथ, इसने अनुकूल और व्यवस्थित वित्तपोषण की स्थिति और बहाली के लिए एक अनुकूल वातावरण की सुविधा प्रदान की। चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान जी-एसएपी सहित खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से प्रणाली में डाली गई कुल चलनिधि ₹2.37 लाख करोड़ थी, जबकि पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹3.1 लाख करोड़ की चलनिधि डाली गई थी। मौजूदा चलनिधि के ओवरहैंग को देखते हुए, जीएसटी मुआवजे के लिए अतिरिक्त उधार लेने की आवश्यकता का अभाव और बजट अनुमानों के अनुरूप बढ़ते हुए सरकारी खर्च के कारण प्रणाली में चलनिधि के अपेक्षित प्रसार से, इस समय आगे जी-एसएपी परिचालन करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, रिज़र्व बैंक चलनिधि स्थितियों के अनुसार जब भी आवश्यक हो जी-एसएपी शुरू करने के लिए तैयार रहेगा और ऑपरेशन ट्विस्ट (ओटी) और नियमित खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) सहित अन्य चलनिधि प्रबंधन कार्यों को लचीले ढंग से करना जारी रखेगा।
20. जनवरी 2021 के मध्य से सामान्य चलनिधि परिचालन की बहाली के साथ, 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों को चलनिधि प्रबंधन ढांचे के तहत मुख्य साधन के रूप में नियोजित किया गया है। वीआरआरआर के लिए बाजार की भूख उत्साही रही है। इसके अलावा, स्थायी दर रिवर्स रेपो की तुलना में वीआरआरआर द्वारा प्रस्तावित उच्च पारिश्रमिक पहले की अपेक्षा इसे आकर्षक बना रहा है। बाजार की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित

तरीके से पाक्षिक आधार पर 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी करने का प्रस्ताव है: आज ₹4.0 लाख करोड़ जो पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है; 22 अक्टूबर को ₹4.5 लाख करोड़; 3 नवंबर को ₹5.0 लाख करोड़; 18 नवंबर को ₹5.5 लाख करोड़; और 3 दिसंबर को ₹6.0 लाख करोड़। इसके अलावा, विकसित चलनिधि स्थितियों के आधार पर - विशेष रूप से पूंजी प्रवाह की मात्रा, सरकारी व्यय की गति और ऋण उठाव - आरबीआई 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामियों को 28-दिवसीय वीआरआरआर नीलामियों के साथ समान कैलिब्रेटेड पद्धति के साथ जोड़ने पर भी विचार कर सकता है। आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर अलग-अलग राशि में फाइन-ट्यूनिंग परिचालन करने के लिए लचीलापन भी बरकरार रखता है। इन सभी परिचालनों के साथ भी, दिसंबर 2021 के पहले सप्ताह में स्थायी दर रिवर्स रेपो के तहत अवशोषित चलनिधि तब भी लगभग ₹ 2 से 3 लाख करोड़ होगी।

21. मैं इस बात को दोहराना और जोर देना चाहता हूँ कि वीआरआरआर नीलामी मुख्य रूप से हमारे चलनिधि प्रबंधन कार्यों के हिस्से के रूप में चलनिधि को पुनर्संतुलित करने के लिए एक उपकरण है और इसे निभावकारी नीति रख के पलटाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आरबीआई यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक बहाली की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए पर्याप्त चलनिधि हो। रिज़र्व बैंक सरकार के उधार कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए बाजार का समर्थन करना जारी रखेगा। इसके अलावा, जनहित के रूप में आय वक्र के क्रमिक विकास पर हमारा ध्यान भी जारी है।

अतिरिक्त उपाय

22. इस पृष्ठभूमि में और समष्टिआर्थिक स्थिति और वित्तीय बाजार की स्थितियों के हमारे निरंतर मूल्यांकन के आधार पर, आज कुछ अतिरिक्त उपायों की भी घोषणा की जा रही है। इन उपायों का विवरण मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और नियामक नीतियों (भाग-बी) पर वक्तव्य में निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उपाय इस प्रकार हैं।

लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए ऑन टैप विशेष दीर्घावधि रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ)

23. मई 2021 में लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए रेपो दर पर ₹10,000 करोड़ का एक विशेष तीन वर्षीय दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ) शुरू किया गया था। यह सुविधा वर्तमान में 31 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध है। लघु व्यवसाय इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को निरंतर समर्थन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, इस सुविधा को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने और इसे ऑन टैप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान समाधान का प्रारंभ

24. उन दूरस्थ स्थानों, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी या तो अनुपस्थित है या मुश्किल से उपलब्ध है, में भी डिजिटल भुगतान को सक्षम करने वाली तकनीकों का परीक्षण करने की एक योजना की घोषणा अगस्त 2020 में की गई थी। पायलट परीक्षणों से प्राप्त उत्साहजनक अनुभव को देखते हुए, पूरे देश में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए एक ढांचा प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इससे

डिजिटल भुगतान की पहुंच का और विस्तार होगा और व्यक्तियों और कारोबारों के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे।

आईएमपीएस में लेन-देन की सीमा को ₹5 लाख तक बढ़ाना

25. त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस) विभिन्न चैनलों के माध्यम से 24x7 त्वरित घरेलू धन अंतरण की सुविधा प्रदान करती है। आईएमपीएस प्रणाली के महत्व को ध्यान में रखते हुए और उपभोक्ता सुविधा को बढ़ाने के लिए, प्रति लेनदेन सीमा ₹ 2 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 लाख करने का प्रस्ताव है।

भुगतान प्रणाली स्पर्श बिंदु की जियो-टैगिंग

26. पूरे देश में भुगतान स्वीकृति (पीए) बुनियादी ढांचे की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना वित्तीय समावेशन के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक रहा है। पीए अवसंरचना की कमी वाले क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए, सभी मौजूदा और नए पीए बुनियादी ढांचे जैसे पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों, त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड, इत्यादि पर सटीक स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए जियो-टैगिंग तकनीक का लाभ उठाने के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। यह पीए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यापक भौगोलिक नियोजन सुनिश्चित करने में रिज़र्व बैंक के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) ढांचे का पूरक होगा।

विनियामक सैंडबॉक्स – नए कोहार्ट के लिए विषय की घोषणा और पहले के विषय के लिए ऑन टैप आवेदन

27. रिज़र्व बैंक के विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) ने अब तक 'खुदरा भुगतान' 'सीमापारीय भुगतान'; और 'एमएसएमई उधार' पर तीन कोहार्ट की शुरुआत की है। फिनटेक इको-सिस्टम को और गति प्रदान करने की दृष्टि से, 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन' पर चौथे कोहार्ट की घोषणा की जा रही है। इसके अलावा, प्राप्त अनुभव और हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, विनियामक सैंडबॉक्स में भाग लेने के लिए पहले के विषयों के लिए 'ऑन टैप' आवेदन की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस उपाय से हमारे देश के फिनटेक इको-सिस्टम में निरंतर नवाचार सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमाओं की समीक्षा और ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा में छूट

28. महामारी के कारण जारी अनिश्चितताओं के बीच राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए ₹51,560 करोड़ की अंतरिम बढ़ाई हुई अर्थोपाय अग्रिम सीमा को 31 मार्च 2022 तक और छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का निर्णय किया गया है। उदारीकृत उपायों को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है, अर्थात् 31 मार्च 2022 तक, एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट (ओडी) के दिनों की अधिकतम संख्या को 36 से 50 दिनों तक और ओडी के लगातार दिनों की संख्या को 14 से 21 दिनों तक बढ़ाया गया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - बैंकों को एनबीएफसी के माध्यम से आगे उधार देने की अनुमति देना - सुविधा जारी रखना

29. एनबीएफसी द्वारा अर्थव्यवस्था के कम सेवा प्राप्त/ सेवा नहीं प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण में देखे गए बड़े संकर्षण को ध्यान में रखते हुए, कृषि, एमएसएमई और आवास को आगे उधार देने के लिए पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को बैंक ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी। यह सुविधा, जो 13 अगस्त 2019 से 30 सितंबर 2021 तक उपलब्ध थी, को और छह महीने के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है।

एनबीएफसी के लिए आंतरिक लोकपाल

30. देश भर में एनबीएफसी की बढ़ती संख्या और पहुंच ने एनबीएफसी के ग्राहकों की सुरक्षा के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न उपायों को आवश्यक बना दिया है। एनबीएफसी के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करने की दृष्टि से, उच्च ग्राहक इंटरफेस वाले एनबीएफसी की कुछ श्रेणियों के लिए आंतरिक लोकपाल योजना (आईओएस) शुरू करने का निर्णय किया गया है।

समापन टिप्पणी

31. यदि पिछले अठारह महीनों के सबसे कष्टकर और कठिन काम ने हमें कुछ सिखाया है, तो वह है अदम्य मानवीय भावना पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए जो हमेशा शक्तिशाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उठती है। हमारे लचीलेपन और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ, हमने सामंजस्य, सुधार और चुनौतियों को अवसरों में बदलना सीख लिया है। जैसे ही हम आर्थिक बहाली की गति को और तेज करते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि जो हासिल किया गया है उसके गर्व में न रहें बल्कि जो किया जाना बाकी है उस पर अथक प्रयास करें। जैसा कि महात्मा गांधी, जिनकी जयंती हमने पिछले सप्ताह मनाई, ने कहा था: "धैर्य खोना युद्ध हारना है"¹।

धन्यवाद। सुरक्षित रहें। स्वस्थ रहें। नमस्कार।

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1001

¹ स्रोत: डी.जी. तेंदुलकर द्वारा पुस्तक महात्मा गांधी- खंड 2 के "महात्मा" द्वारा।